लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक : 16 - 31 अगस्त, 2023 www.haryanasamvad.gov.in अंक - 72

"सत्य, ईश्वर के समान है। जो लोग असत्य बोलते हैं वे ईश्वर के साथ खुद को भी धोखा देते हैं।"
: महात्मा गांधी

भ्रष्टाचार से आज़ादी 3

पराली के धूएं से आज़ादी 5

इक दरख्त ऐसा मुहब्बत का लगाया जाए 8

विकास में सर्वोच्च होगा हरियाणा

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आजादी पर्व पर जताया भरोसा

विशेष प्रतिनिधि

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वर्ष 2047 तक हरियाणा राज्य पूरे देश में विकास के मामले में सर्वोच्च स्थान पर होगा। मुख्यमंत्री 76वीं वर्षगांठ पर फतेहाबाद में आयोजित राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए देश की आजादी में योगदान एवं बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को याद किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूरगामी विजन वाला प्रधानमंत्री बताते हुए कहा कि मोदी जी ने कई चुनौतीपूर्ण विवादों का चुटकियों समाधान कर दिया। प्रधानमंत्री ने देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी बताते हुए उसके पीड़ितों की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाना शुरू किया है। वन रैंक-वन पेंशन की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करके वीर सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर 21वीं सदी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है, हरियाणा में वर्ष 2025 तक इस नई नीति को पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य रखा है। सर्जिकल स्ट्राइक, नागरिकता संशोधन कानून, तीन तलाक की कुप्रथा से मुक्ति, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, जल संरक्षण आदि अनेक युग-परिवर्तनकारी कदम उठाए गए हैं।

आत्मनिर्भर होने का संकल्प लें हरियाणावासी

महामहीम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में ज्ञात-अज्ञात देशभक्तों व वीर शहीदों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे महान सांस्कृतिक परम्पराओं, उच्च नैतिक एवं मानवीय मूल्यों पर चलते हुए खुशहाल एवं आत्म निर्भर हरियाणा तथा नया भारतवर्ष बनाने का संकल्प लें।

महामहीम ने सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं से आह्वान किया कि वे समाज सेवा के कार्यों में स्वैच्छा से आगे आयें और विभिन्न सामाजिक मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक कर अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें।

सिस्टम को दुरुस्त किया

मुख्यमंत्री ने प्रदेश का विकास करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि वर्ष 2014 में जब हमने जनसेवा का दायित्व संभाला तो लक्ष्य हर हरियाणवी के हितों की सुरक्षा करना था। हमने पूरे प्रदेश के लोगों को अपना परिवार माना है। किसी धर्म, सम्प्रदाय, जाति, क्षेत्र आदि के भेदभाव के बिना हरियाणा एक-हरियाणवी एक के भाव से सब नागरिकों और सब क्षेत्रों का समान विकास प्राथमिकता रहा है। पिछले 9 वर्ष हरियाणा में सद्भाव, सौहार्द, समान विकास, समरसता, सहिष्णुता के साथ-साथ उन बदलावों के साक्षी रहे हैं, जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। इसके लिए समदृष्टि के साथ-साथ पुराने पड़ चुके सिस्टम की उन अड़चनों को दूर करना जरूरी था, जो जनसेवा और जनता के बीच दीवार बनकर खड़ी हो चुकी थी।

कैनवस पर विभाजन की दास्तां

साहित्य और कला ने अपनी समसामयिक पीड़ाओं को किस तरह कूची और कलम से कैनवस और कागज़ पर उतारा, उसके दो उदाहरण हैं- अमृता प्रीतम और चित्रकार पाराशर। अमृता ने लाहौर से रेल द्वारा भारत में प्रवेश करते हुए 'अज आखां वारिसशाह नूं/ कितो कबरां विचों बोल...' और पाराशर ने बलदेव नगर कैम्प अम्बाला के शरणार्थी-शिविर में वहां आ बसे शरणार्थियों की पीड़ा को 'कैनवस' पर चितेरा। उस समय की व्यथा कथा की प्रामाणिक दस्तावेज़ हैं इन दोनों की कृतियां।'

पाराशर वर्ष 1947 से 1949 तक दो वर्ष इस शरणार्थी-शिविर के कमांडेंट रहे थे। दरअसल, घर उजड़ने एवं जड़ों से उखड़ने का सिलसिला 1947 में ही आरंभ हो गया था। हालांकि सर्वाधिक शरणार्थी करनाल-कुरुक्षेत्र के चार शरणार्थी-शिविरों में टिके थे, मगर 'बलदेव नगर कैम्प' इनका पहला ठिकाना था।

पाराशर को तब शायद यह मालूम नहीं था कि वह एक ऐसे अध्याय को कैनवस पर उतार रहे हैं जो एक नए देश का इतिहास बनेंगे। पीड़ा, हताशा, सबकुछ खो बैठने की अनुमति, अनिश्चित भविष्य, यानि बीते हुए कल, आज और कल आने वाले अनिश्चित की कल वेदना को भागते हुए चेहरे।

शेष पृष्ठ 2 व 8 पर

विजयी विश्व तिरंगा प्यारा

'ऐ मेरे वतन के लोगो, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।' स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने यह गीत सबसे पहले 27 जनवरी 1963 को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में गाया था। गीत बेशक पुराना है लेकिन इसकी व्यंजना आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। गीत के स्वर कानों में पड़ते हैं तो शरीर का रोयां-रोयां देशभक्ति के भाव से सराबोर होने लगता है।

आज़ादी के विषय पर 1957 में बनी फिल्म 'नया दौर' का गाना 'ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का' आज भी लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को तरोताजा कर देता है। साहिर लुधियानवी द्वारा लिखे इस गीत को मोहम्मद रफ़ी और बलबीर ने आवाज़ दी थी। 1967 में आई 'उपकार' फिल्म में महेंद्र कपूर द्वारा गाया गीत 'मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती' आज जब भी, जहां भी बजता है, वहां की आबोहवा में राष्ट्रप्रेम की सुगंध घोल देता है।

इन्हीं भावों को स्पर्श करता एक गीत है 'अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों'। फिल्म 'हकीकत' के लिए मोहम्मद रफी द्वारा गाए गए इस गीत ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। मशहूर गीतकार कैफ़ी आज़मी ने इस गीत के बोल लिखे थे।

देशभक्ति के भावों का संचार करने वाले इन गीतों की श्रेणी में अनेक गीत हैं जिन्होंने देशवासियों के दिलों में राष्ट्रप्रेम की भावना को प्रगाढ़ करने का काम किया और कर रहे हैं। किसी भी स्कूल, कालेज या अन्य प्रतिष्ठान में समारोह होता है तो इन गीतों को विशेषतौर से बजाया जाता है। राष्ट्रगान की मधुर वाणी से दिलों में स्वतः देशभक्ति की भावना जागृत होने लगती है।

देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की लौ मध्यम न हो, इसे और बल मिले इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' मनाया गया। इस कड़ी में 'हर घर तिरंगा' एक विशेष अभियान रहा। गौरतलब है कि दिलो दिमाग में जब देश के प्रति निष्ठा की प्रधानता होती है तो समाज में एकता, प्रेम, सौहार्द, सहयोग एवं प्रगति का संचार होता है।

- मनोज प्रभाकर

हरियाणा में सफल रहा अमृत महोत्सव

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. अमित अग्रवाल ने बताया कि 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के दौरान 'मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन' अभियान चलाया गया। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया तथा हर गांव से मिट्टी यात्रा शुरू की गई। गांवों से कलश में मिट्टी ली गई। राज्य के 143 खण्डों से मिट्टी लेकर 'कर्तव्य पथ' दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम में ले जाया गया। गांवों में अमृत सरोवर के किनारे बनाई गई अमृत वाटिकाओं में पौधे लगाए गए तथा पांच प्रण लेकर राष्ट्रगान का उद्घोष हुआ।

संपादकीय

धीरे-धीरे फिर से मेवात में सौहार्द

मेवात एक ऐसा ज़िला था जो शांति प्रिय रहा था। मगर कुछेक अवांछित तत्वों ने इसकी शांतिपूर्ण छवि को दाग़दार बना दिया। फिर भी वहां शांति स्थापना में लम्बा समय नहीं लगा और मुख्यमंत्री व गृह मंत्री की दूरदर्शी नीति के परिणामस्वरूप स्थिति कुछ ही दिनों में पटरी पर लौट आई। प्रार्थना करें कि वहां स्थितियां पहले से भी बेहतर हो जाएं और पुराना सौहार्द फिर से बहाल हो।

इधर, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश में विकास की गति सक्रिय बनी रही है। नूंह जिला में साइबर क्राइम को अपना पेशा बनाने वाले अपराधियों पर नकेल कसने के लिए हरियाणा पुलिस बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। अप्रैल माह में पुलिस ने नूह में साइबर जालसाजों के ठिकानों पर एक साथ रेड कर देश भर में लगभग 100 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का खुलासा किया था। यह भारत में अपनी तरह की अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी थी और इसमें कुल 5,000 जवान और अधिकारी शामिल थे जिन्होंने नूंह के 14 गांवों में फैले 320 साइबर अपराधियों के ठिकानों पर छापे मारे थे।

छापेमारी के दौरान 65 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और अन्य 25 साइबर अपराधियों को छापेमारी से पहले और छापेमारी के बाद की अवधि में गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 56 मोबाइल डिवाइस और पांच माइक्रो एटीएम मशीनों सहित बड़ी संख्या में आईटी डिवाइस जब्त किए गए। 739 फर्जी सिम, 3.7 फर्जी बैंक खाते और 199 यूपीआई हेंडल के विवरण सहित कई फर्जी दस्तावेजों का खुलासा हुआ। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों नूह में हुई हिंसा की आड़ में इस छापेमारी के दौरान जुटाए गए सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई और साइबर पुलिस स्टेशन पर सुनियोजित हमला किया गया। नूंह का ये साइबर पुलिस स्टेशन दो साल पहले ही बन कर तैयार हुआ है। साइबर स्टेशन में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और दूसरे आपराधिक दस्तावेज थे और उपद्रवियों को मकसद इनको बर्बाद करना भी था। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हर पुलिस स्टेशन में एक कुल मिलाकर 318 साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किए हैं। इन पर लगभग 700 कर्मी तैनात हैं। सरकार की जागरुकता वहां की स्थितियों को और भी बेहतर बनाएगी।

-डॉ. चन्द्र त्रिखा

मेरी माटी-मेरा देश

'मेरी माटी-मेरा देश' अभियान के तहत हरियाणा से 311 कलशों में मिट्टी भर कर दिल्ली ले जाया जाएगा जिससे अमृत वाटिका विकसित होगी। यह अभियान स्वतंत्रता, एकता और अखंडता में योगदान देने वाले नायकों को समर्पित है।

स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि अभियान के तहत दिल्ली में अमृत वाटिका बनाने के लिए देश के कोने -कोने से 7,500 कलशों में मिट्टी भर कर ले जाएंगे। यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया यह अभियान अब जन-जन का अभियान बन चुका है। देश के लिए अपना जीवन न्योछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीदों के गांवों से मिट्टी लेकर कलश में एकत्रित की जा रही है।

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
स्टाफ राइटर : संगीता शर्मा
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

शरणार्थी शिविरों में अटका था प्रारब्ध

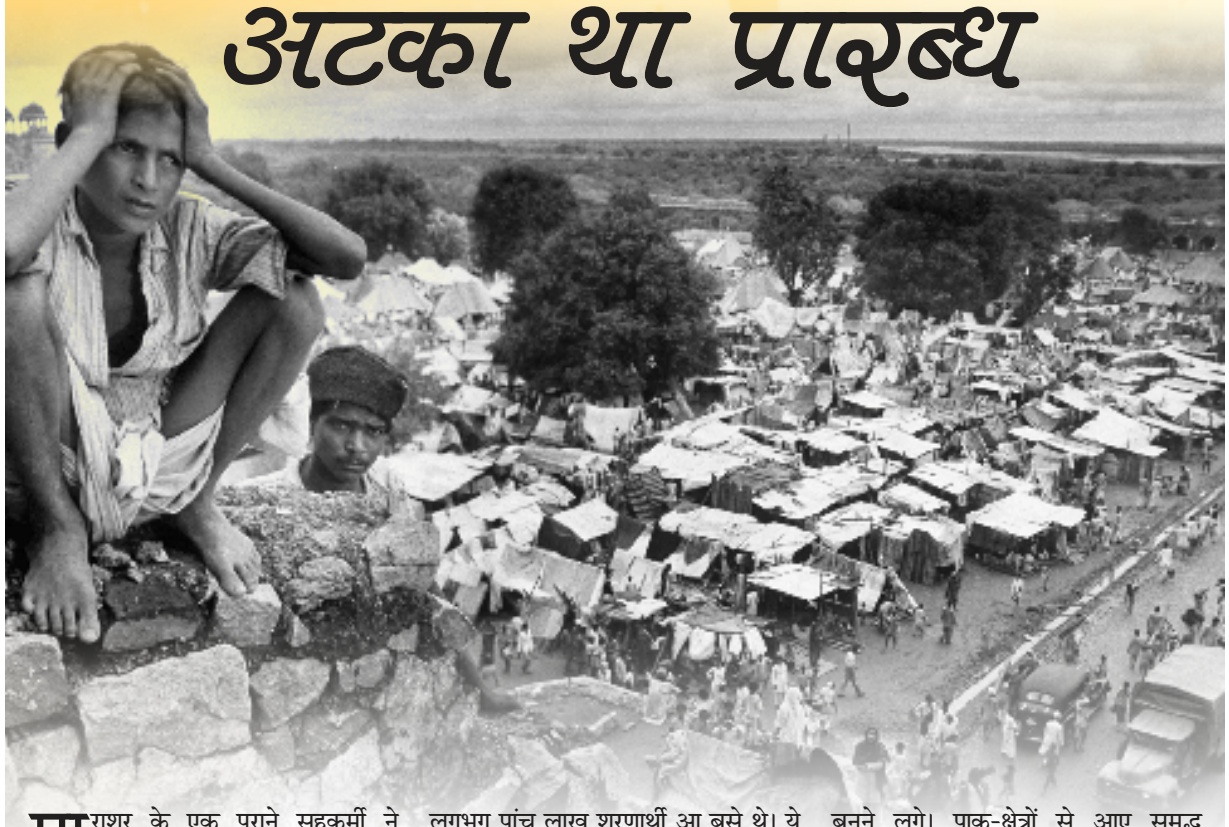

पाराशर के एक पुराने सहकर्मी ने बताया था कि इस चित्रकार ने उन्हीं दिनों एक ऐसी शरणार्थी औरत का चित्र भी बनाया था जो उन दिनों 'सकते' की स्थिति में थी। पूरी तरह गुमसुम। परिवार वाले उसे सामने बैठकर रोटी खिलाते। उसकी नज़र कहीं सूने में गढ़ी रहती। वह सिर्फ़ मुंह खोलती, रोटी का एक-एक ग्रास उसके मुंह में मां ठूस देती और वह धीरे-धीरे उसे चबाने लगती। पाराशर ने एक बार उसकी मांग से पूछा, यह ऐसी गुमसुम क्यों है? तो मां ने आसपास के लोगों की नज़र चुनाकर आंखों में आंसू भरते हुए बताया था, 'क्या पूछते हो साहब! क्या बताऊं। इसे उन दिनों कुछ गुण्डे उठाकर ले गए थे। बुरी हालत कर दी थी, फिर अधमरी को हमारे सामने फैंक कर चले गए थे। तब से यह ऐसी ही गुमसुम है। इसे शौच वगैरह के लिए भी उठाकर ले जाती हूं। क्या करूं साहब! मां हूं न। मैं इसे काफिले के साथ ही ले आई। ज़िद करती थी इसे वहीं मरने के लिए छोड़ दें। मगर न बाप माना न मैं। बस ले आए। आप कुछ कोशिश करो साहब, एक बार खुलकर रो ले तो शायद कुछ ठीक हो जाए। आखिर कब तक गुमसुम बैठी रहेगी?'

पाराशर उस समय स्वयं भावुक हो गए। अपनी ही आंखों से आंसू बहने लगे थे। उन्होंने उस मां के कंधे पर हाथ रखा, 'हौसला रखो। मैं उस पर वक्त लगाऊंगा।' पाराशर ने उस लड़की को समझने, पुचकारने दुलारने की कोशिश की। उसे यह भी कहा, 'मैं तुम्हारा बाप हूं। बाप के सामने दुखड़ा रो लेगी तो मन हल्का हो जाएगा।' मगर पाराशर सफल न हो पाए। उसकी उदासी को कैनवस पर उतार लिया। मगर कुछ दिन बाद ही पता चला, लड़की ने कैम्प के पास ही लगी झाड़ी से कुछ ज़हरीले पत्ते खा लिए। कैम्प के डॉक्टर ने बताया था, लड़की ने धतूरे का सेवन मात्रा से अधिक कर लिया था। बचने की उम्मीद नहीं थी। आखिर दो दिन बाद वह चल बसी। उसकी चिता को बाप ने ही आग दी। पाराशर स्वयं भी मौजूद थे। उस महान चितेरे के एक मित्र ने जब सारी बात सुनाई तो उसकी अपनी आंखों में भी गहरी नमी उतर आई थी।

कुरुक्षेत्र का शरणार्थी शिविर

कुरुक्षेत्र के शरणार्थी शिविर, पंजाब-हरियाणा के सबसे बड़ा शिविर थे। यहां लगभग पांच लाख शरणार्थी आ बसे थे। ये शिविर कुरुक्षेत्र, नीलोखड़ी व करनाल तक फैले हुए थे। इन क्षेत्रों में सभी उपलब्ध सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों, धर्मशालाओं, महिला आश्रमों व संतों के डेरों में टैंट लगा दिए गए थे। भोजन की व्यवस्था में कुछ डेरों व गुरुद्वारों की सेवाएं भी ली गई थीं।

प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू अप्रैल 1948 में कुरुक्षेत्र में शिविरों का निरीक्षण करने आए थे। इन दिनों यथासंभव शरणार्थियों को वे आवास व भूखण्ड आवंटित किए जा रहे थे जो यहां से पलायन करने वाले मुसलमानों की सम्पत्ति थे। पाक-पंजाब से आने वालों में जिला झंग, लायलपुर, मिंटगुमरी, शेखूपुरा, मुल्तान, बहावलपुर, शाहपुर, अहमदपुर आदि क्षेत्रों से आए थे। ज़ाहिर था वहां की सामाजिक संरचना, संस्कृति, लोक-कथाएं, लोकगीत खानपान, पहरावा आदि भी उनके साथ ही आ गए थे। यहीं से कुछ लोग समीपस्थ स्थित पिहोवा व कैथल के क्षेत्रों में चले गए और कुछ शाहबाद मारकंडा, लाडवा, रादौर आदि क्षेत्रों में जा सके।

यमुनानगर/फ़रीदाबाद

विभाजन-वर्ष यानि 1947 से पहले यमुनानगर एक छोटा सा कस्बा था। लेकिन विभाजन के बाद बड़ी संख्या में शरणार्थियों को यहां ठिकाने आवंटित हुए। इसी तर्ज़ पर फ़रीदाबाद में वर्तमान पाक के 'उत्तर पश्चिम फ्रंटीयर' जिले से आने वाले शरणार्थियों को शरण मिली। वर्ष 1947 तक यह भी एक छोटा सा शहर था। अब यमुनानगर और फ़रीदाबाद दोनों का शुमार बड़े नगरों व औद्योगिक बस्तियों के रूप में होता है। इन शहरों को शरणार्थियों ने ही तरजीह दी क्योंकि दिल्ली में या जीटी रोड पर स्थायी ठिकाने बनाने उनके वित्तीय सीमा से बाहर थे। इन दोनों शहरों में उद्योग धंधे भी इसलिए तेज़ी के साथ पनपे क्योंकि सवाल रोज़गार के नए अवसर देने का भी था।

फ़रीदाबाद का एनआईटी (न्यू इंडस्ट्रीयल टाउनशिप क्षेत्र) 1950 में स्थापित हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61) के दौरान यहां विकास में तेज़ी आई। शरणार्थियों के लिए मॉडल टाऊन, तहसील कैम्प, कच्चा कैम्प, नहर वाला कैम्प, अठवट शिविर और अनेक नए स्कूलों व कॉलेजों में शिविर लगे जो धीरे-धीरे स्थायी आवास का आधार बनने लगे। पाक-क्षेत्रों से आए समृद्ध उद्यमियों ने यही मेहनत-मशक्कत का निवेश किया और सरकारी मदद से अपनी औद्योगिक बस्तियां तेजी के साथ विकसित कर लीं।

जिला रोहतक

इस ज़िले में पश्चिमी पंजाब से आए शरणार्थी परिवारों को व्यापक स्तर पर शरण दी। यहां से लगभग 1.63 लाख ने पलायन किया था। इनमें से अधिकांश अफ़गान, बलोच, राजपूत और शेख थे। इनका स्थान पाक-क्षेत्रों झंग, मुल्तान, मुज़फ़्फ़रगढ़ और लायलपुर से आए लोगों ने ले लिया।

सोनीपत भी तब रोहतक जिले में ही था। यहां बसे शरणार्थियों में 858 परिवार झंग क्षेत्र से थे, 257 परिवार मुल्तान से आए थे, मुज़फ़्फ़रगढ़ से 11068, लायलपुर से 189 और अन्य क्षेत्रों से 1698 परिवार विस्थापित हुए। रोहतक तहसील में झंग से आए शरणार्थियों की संख्या सर्वाधिक थी। कुल 18984 लोग उसी क्षेत्र से आकर बसे थे। अन्य शरणार्थियों में 856 मुल्तान से, 620 मुज़फ़्फ़रगढ़, 1389 लायलपुर से और 1214 अन्य स्थलों से थे। शेष में से गोहाना तहसील में ज़्यादातर लोग बसे जबकि लगभग 70,194 लोगों ने फुटकर स्थानों पर अर्थात् जहां भी नहर किनारे, सड़क किनारे या खेत में रैन-बसेरा मिला, शरण ले ली। गांवों में ज़्यादातर वे लोग बसे, जो गांवों से ही उजड़कर आए थे। उन्हें पुनर्वास एवं विस्थापन के समय थोड़ी-थोड़ी ज़मीनें आवंटित कर दी गई ताकि वे अपने पुराने एवं पुश्तैनी कृषि-धंधे में लग सके।

इस आवंटन के मध्य अनेक अनियमितताएं भी हुईं जो शायद स्वाभाविक थीं। कुछ लोगों ने स्वयं को बड़ा ज़मींदार बताया था और उस आधार पर ज़्यादा ज़मीनें भी आवंटित करा लीं। जो वाकई अतीत में बड़े ज़मींदार थे, उनमें से कई अपने पुराने स्तर के करीब पहुंचने से भी वंचित भी रह गए। इन अनियमितताओं की व्यापक स्तर पर जांच 1955 में शुरू हुई। तब तक पाकिस्तान से राजस्व-रिकार्ड भी आ चुका था। उसके दृष्टिगत अनेक आवंटन रद्द हुए और जिनसे न्याय नहीं हो पाया था उन्हें अब अपना अधिकार पाने का अवसर मिल गया।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिरसा के इंडस्ट्रियल एरिया में 6 करोड़ 20 लाख की लागत से बने अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) का उद्घाटन किया।

हरियाणा सरकार की ओर से पुलिस विभाग के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत सिंह कपूर को हरियाणा राज्य का नया महानिदेशक नियुक्त किया है।

भ्रष्टाचार से आज़ादी

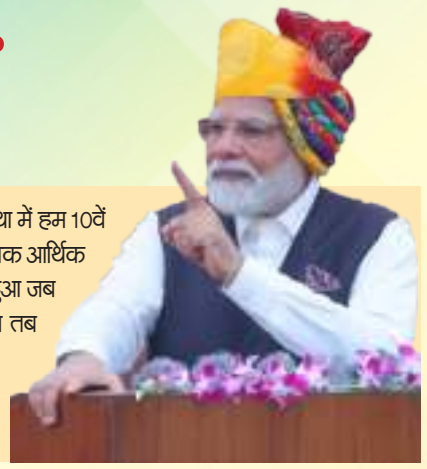

'2014 में जब हम सत्ता में आए तो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में हम 10वें स्थान पर थे। आज 140 करोड़ भारतीयों के प्रयास से हम वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं। यह ऐसे ही नहीं हुआ जब भ्रष्टाचार के राक्षस ने देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया था तब हमने इसे रोका और एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई।'

- नरेंद्र मोदी, लाल किले की प्राचीर से

मनोज प्रभाकर

भ्रष्टाचार के मामलों में मनोहर सरकार शुरू से ही जीरो टोलरेंस पर चल रही है। सरकारी सिस्टम में तीन दो पांच करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जा रहा है चाहे वह कितने ही बड़े कद का हो। अधिकारी कर्मचारी या अन्य सभी नप रहे हैं। हेराफेरी की पुरानी आदतों को छुड़वाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस मामले में लोगों से सहयोग की अपील की है। कहा गया है कि जब प्रदेश का हर नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा नहीं होगा तब तक इस बुराई पर काबू नहीं पाया जाएगा। समाज व प्रदेश की भलाई के लिए लोगों को स्वार्थ की भावना से ऊपर उठना होगा।

हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो राज्य सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा के विज़न को साकार करने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों को सम्मानित कर रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो, हरियाणा के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने हाल ही में पंचकूला रेंज के 17 शिकायतकर्ताओं को 'सम्मान पत्र' देकर सम्मानित किया। इन्होंने आगे आकर भ्रष्टाचार के खिलाफ़ शिकायत दर्ज़ करके असाधारण साहस का प्रदर्शन किया है। इसी तरह के सम्मान समारोह अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित एसीबी की सभी रेंज कार्यालयों में भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें कुल 132 शिकायतकर्ताओं को सम्मानित किया गया।

कपूर ने भ्रष्ट अधिकारियों को बेनकाब करके एक ईमानदार समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए शिकायतकर्ताओं की सराहना करते हुए उन्हें असली नायक बताया। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस दौरान उनके समक्ष अगर किसी तरह का उत्पीड़न या दबाव आता है तो उससे तुरंत निपटा जाएगा। उन्होंने शिकायतकर्ताओं को ऐसे मामलों की रिपोर्ट संबंधित जांच अधिकारी या टोल-फ्री नंबर 1800-180-2022 पर करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे एसीबी की ओर से तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। भ्रष्टाचार एक सामाजिक बीमारी है जिसे सामूहिक आवाज़ उठाकर ही खत्म किया जा सकता है।

एसीबी ने वर्ष 2023 में अब तक रिकॉर्ड 100 ट्रैप मामले दर्ज़ किए हैं और 99 से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कई क्लास-1 और 2 अधिकारी भी शामिल हैं। ट्रैप मामलों के दौरान शिकायतकर्ताओं को अपनी जेब से खर्च करने की जरूरत नही है। निर्धारित फंड से जरूरतमंद शिकायतकर्ताओं को धनराशि वितरित की जा रही है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ यहां करें शिकायत

एसीबी ने लोगों से आग्रह किया कि वे सरकारी विभागों के अधिकारियों द्वारा सरकारी कार्यों की एवज में रिश्वत मांगने की किसी भी घटना की तुरंत रिपोर्ट करें। इस संबंध में शिकायत टोल-फ्री नंबर 1800-180-2022 और 1064 के साथ-साथ व्हाट्सएप नंबर 094178-91064 के माध्यम से की जा सकती है।

चोर उचक्कों से आज़ादीः मनोहर सरकार की करिश्माई कार्यप्रणाली देखिए कि सूबे में चोरी चकारी की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। चोर उचक्कों को पता चल गया है कि कोई भी आदमी अगर उनको शक के बिनाह पर भी 112 नंबर डायल कर देगा तो शामत आ जाएगी। प्रदेश के लोग इस पुलिस सहायता सेवा का खूब लाभ ले रहे हैं।

भाई भतीजावाद से आज़ादी

वोट डालने की आज़ादी, चुनाव लड़ने की आज़ादी व सत्ता में पहुंचने की आज़ादी भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। मगर सत्ता में स्थापित होकर भाई भतीजावाद की राजनीति करना भ्रष्टाचार नामक बुराई से कम नहीं है। ये दोनों बुराइयां एक ही वर्ग से हैं। या यूं कहें कि दोनों मामा-फूफी की हैं। हरियाणा की राजनीति में लंबे अर्से से इन दोनों 'महारानियों' का जलवा चला आ रहा था। इसी जलवे के चलते सूबे की जनता भेदभाव की शिकार होती चली गई। अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब होते चले गए।

इन लंबी बीमारियों के चलते लोग न केवल पीड़ित हुए बल्कि व्यवस्था से नाउम्मीद होते चले गए। मजे की बात तो यह है इस व्यवस्था को ही लोगों ने व्यवस्था मान लिया था। मनोहर लाल मुख्यमंत्री न बनते तो उपरोक्त बीमारियों को कानूनी जामा पहनाया दिया गया होता।

बहुत पुरानी बात नहीं है, लोगों को आज भी भाई भतीजावाद की यादें स्मरण हैं। कभी किसी रिश्ते में तो कभी किसी नाते में सत्ता का दोहन होता रहा। प्रदेश का बड़ा व आम वर्ग हाशिये पर जाता गया। इन विकट परिस्थितियों में जन्म हुआ पर्ची व खर्ची का। जो लंबे समय तक चला।

मनोहर लाल ने वर्ष 2014 में आते ही 'हरियाणा एक हरियाणवी एक' का नारा दे दिया था। साफ एलान कर दिया था कि प्रदेश में किसी भी मोर्चे पर भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। अपने मंत्रियों व अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दे दिए गए थे।

भाई भतीजावाद होता क्या है ? इसके जरिए जहां भी दो पैसे के फायदे या काम की बात होती है, वह सब सत्ता में बैठे नेताओं व उनके कार्यकर्ताओं के हिस्से में होती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस घुण की बीमारी से भली भांति परिचित थे, उन्होंने आते ही 'सबका साथ सबका विकास' का नारा दे दिया। अंत्योदय के भाव से सुदूर बैठे परिवारों को भी समान दृष्टि से देखा जा रहा है और उन्हें योजनाओं का फायदा पहुंचाया जा रहा है।

कहने-सुनने की आज़ादी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 26 अक्टूबर, 2014 को सत्ता संभालते ही प्रदेश की राजनीति की दशा व दिशा बदलने की पहल करते हुए कहा था कि उनके लिए राजनीति स्वार्थ नहीं जनसेवा है। 'हरियाणा एक-हरियाणवी एक' उनकी राजनीति का मूलमंत्र है। उसी पर चलते हुए 25 दिसंबर, 2014 को सुशासन दिवस के अवसर पर आरंभ की गई सीएम विंडो व्यवस्था लोगों को खूब रास आई है। आम लोगों को इनके माध्यम से कहने व सुनने की आज़ादी मिली है। वरना पहले कहां किसी की सुनवाई होती थी और किसे बोलने दिया जाता था? कोई भी व्यक्ति अपने मन की बात किसी भी राजकीय प्लेटफार्म पर अपनी बात रख सकता है।

पिछले साढ़े 8 वर्षों की अवधि में अब तक 11 लाख 50 हजार 958 लोगों ने सीएम विंडो पर अपनी शिकायत भेजी जिनमें से 10 लाख 58 हजार 996 शिकायतों का समाधान किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सत्ता की अपनी दूसरी पारी में लोगों के बीच जाकर पंच परमेश्वर की तरह जनसंवाद कार्य' म की शुरुआत की है। ग्राम दर्शन पोर्टल पर कोई भी ग्रामीण अपनी बात रख सकता है या गांव से संबंधित शिकायत, मांग या सुझाव दे सकता है। संबंधित विभाग के अधिकारी उन पर संज्ञान लेते हैं।

ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि गांवों से दूर बनी ढाणियों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र योजना के अंतर्गत टीबी से ग्रस्त पांच मरीजों को गोद लिया है। पंचकूला सीएमओ डॉ मुक्ता कुमार ने मरीजों को पोषण आहार किट प्रदान की।

खाद्यान्न संकट से आज़ादी

एक राष्ट्र- एक राशन कार्ड योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर राशन कार्डधारक को देश में कहीं भी राशन प्राप्त करने की सुविधा देने के लिए 'एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड' योजना दी है। पहले रोज़गार अथवा किसी अन्य कारण से अपने मूल निवास से दूर जाकर रहने वाले गरीब परिवारों को राशन नहीं मिल पाता था। अब देश का कोई भी नागरिक अपना आधार कार्ड दिखाकर कहीं भी किसी भी राशन डिपो से अपना राशन प्राप्त कर सकता है।

राशन कब आएगा, आएगा तो कब बंटेगा की जानकारी लाभार्थियों के पास नहीं होती थी। अब सभी के मोबाइल पर संबंधित जानकारी पहुंच जाती है। डिपो पर फिंगर प्रिंट के जरिए राशन का आवंटन हो जाता है। इतना ही नहीं इस सिस्टम से बहुत बड़ी हेराफरी भी बंद हो गई है। याद होगा पहले के सिस्टम के तहत कई कई माह तक राशन नहीं बंटता था। चर्चा रहती थी कि राशन का सामान सीधे मीलों में या बड़ी दुकानों में पहुंच गया है। कोई शिकायत कर्ता नहीं था, था तो कोई सुनवाई भी नहीं होती थी। शायद यही वजह थी कि राशन का डिपो लेने के लिए विभाग में बड़ी बड़ी सिफारिशें चलती थी। मनोहर सरकार ने सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन करके व्यवस्था को सहज, सरल व पारदर्शी किया है। डिपो धारकों का कमीशन 1.50 रुपए से बढ़ाकर 2 रुपए किया गया है।

'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न' योजना के तहत प्रदेश के लगभग 32 लाख परिवारों को पीडीएस योजना का लाभ मिल रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने सिस्टम में बदलाव किया है। सभी कार्य ऑनलाइन तरीके से हो रहे हैं, इससे लाभार्थियों के साथ साथ डिपो धारकों को भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता।

डिपुओं पर पी.ओ.एस मशीन

पहले लोगों की शिकायत होती थी कि हमें राशन नहीं मिला, राशन कम मिला, राशन कोई और ले गया या राशन कार्ड कट गया, ऐसी सभी शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने ई.पी.डी.एस पोर्टल की शुरुआत की है। इसके तहत उचित मूल्यों की 9,434 दुकानों पर स्वचालित पी.ओ.एस मशीनों के द्वारा उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे आवश्यक वस्तुओं का शत-प्रतिशत वितरण बायोमेट्रिक आधार पर प्रमाणीकरण करने के बाद किया जा रहा है। अब कोई भी अपात्र व्यक्ति फर्जी तरीके से राशन प्राप्त नहीं कर सकता।

महिलाएं चलाएंगी राशन डिपो

हरियाणा सरकार की नई नीति के तहत यह तय किया है कि उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में 33 प्रतिशत महिलाओं को राशन की दुकानें दी जाएंगी। जो नई राशन की दुकानें खुलेंगी, उनके लिए यदि महिलाएं आवेदन करती हैं तो प्राथमिकता आधार पर उनको दुकानें आवंटित की जाएंगी। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फेयर प्राइस शॉप के पोर्टल की शुरुआत की है। पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 3,224 नए डिपो के लाइसेंस दिए जाएंगे। जिनमें से 2,382 राशन डिपो महिलाओं को दिए जाएंगे।

लाल डोरे से आज़ादी

आवंटन एवं बंटवारे के मकड़जाल में फंसी गांवों की जमीन को उक्त योजना से बड़ी राहत मिली है। चप्पा-चप्पा जमीन की निशानदेही हो गई है। अब लगभग स्पष्ट हो गया है कि किस जमीन का कौन मालिक है। ऐसा पहली बार हुआ है। प्राचीन समय से चले आ रही जमीनी विवाद की समस्या लगभग समाप्त हो गई है।

राज्य के 44,212 वर्ग किमी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जीआईएस मानचित्र प्रणाली की परियोजनायें पूरे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए आरम्भ की गई। यह प्रणाली भूमि के सटीक सीमांकन तथा परिवर्तनों का पता लगाने और अति' मणों की पहचान करने में सहायता करेगी। राज्य के 6260 गांवों में लाल डोरे में मानचित्रण का कार्य तथा डाटा प्रक्रिया भारत सर्वेक्षण विभाग द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। इनमें से 6 जुलाई 2022 तक 6,248 गांवों के लाल डोरा स्थित 23.65 लाख से अधिक अचल सम्पत्तियों के भू-स्वामियों को मालिकाना अधिकार तथा पंजीकृत टाइटल डीड वितरित की जा चुकी हैं।

वर्तमान में हर भू-स्वामी किसी भी समय अपनी सम्पतियों और भू-रिकार्ड का ब्यौरा आनलाईन प्राप्त कर सकता है। इसमें दस्तावेजों का पंजीकरण, इंतकाल, जमाबंदी रिकार्ड का रख रखाव, ई-खसरा गिरदावरी, रोजनामचा व स्वामित्व रिकार्ड की नकल आदि जारी किये जाते हैं ।

रजिस्ट्री के बाद स्वतः होगा इंतकाल

राज्य में अब तहसीलदारों के अलावा एसडीएम और डीआरओ को भी अपनी तहसीलों में संपत्ति के पंजीकरण के लिए अधिकृत किया गया है। जल्द ही एक नई प्रणाली शुरू की जाएगी जिसके तहत संपत्ति की रजिस्ट्री किसी भी जिले में कहीं भी हो सकेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई-गवर्नेंस की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए संपत्ति के इंतकाल की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है।

बेटियों की उड़ान, बढ़ा प्रदेश का मान

संगीता शर्मा

हरियाणा की बेटियों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने अथाह परिश्रम से देश-प्रदेश का मान बढ़ाया है। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री सुश्री कल्पना चावला, प्रथम महिला पायलट प्रियंका बेनीवाल, प्रथम महिला बी.एस.एफ. में असिस्टेंट कमांडेट सौम्या, मिग-29 उड़ाने वाली देश की प्रथम सिविलियन मेघा जैन, प्रथम महिला रोडवेज बस चालक पंकज देवी, प्रथम महिला पहलवान ओलम्पिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक, प्रथम महिला पहलवान राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता गीता फौगाट, प्रथम महिला पैरालम्पिक रजत पदक विजेता दीपा मलिक, प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वतारोही संतोष यादव, प्रथम महिला वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (डब्लू.डब्लू.ई.) रेसलर कविता दलाल, प्रथम महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता गीतिका जाखड़, प्रथम महिला भीम पुरस्कार विजेता सुनीता शर्मा, प्रथम महिला मिस वर्ल्ड खिताब विजेता मानुषी छिल्लर, हरियाणा की इन बेटियों ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर प्रदेश को गौरवान्वित करने का काम किया है।

कुछ योजनाएं

» राज्य सरकार ने बेटी के विवाह के समय परिवार की मदद करने के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चलाई है। इसके तहत बीपीएल परिवारों को बेटी के विवाह पर 31,000 रुपए से लेकर 71,000 रुपए तक की शगुन राशि दी जा रही है।

» 'सुकन्या समृद्धि योजना' में दस वर्ष की आयु तक की बालिकाओं का खाता डाकखाने में खुलवा सकते हैं। इसमें प्रतिवर्ष 250 रुपए से लेकर 1.50 लाख रुपए तक की राशि जमा करवा सकते हैं।

» उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए हर 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज खोले गये हैं।

» आठ वर्षों में प्रदेश में कुल 72 नये राजकीय कॉलेज खोले गए, जिनमें से 31 लड़कियों के हैं।

» छात्राओं को अपने घरों से शिक्षण संस्थानों तक आने-जाने के लिए 150 कि.मी. की दूरी तक रोडवेज की बसों में मुफ़्त यात्रा सुविधा प्रदान है।

» छात्राओं की यात्रा को सुरक्षित करने के लिए छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना के तहत 211 विशेष महिला बसें चलाई गई हैं।

» बेटियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश में 29 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये गये हैं।

» आईटीआई में पढ़ने वाली लड़कियों को प्रतिमाह 500 रुपए का वजीफ़ा दिया जाता है।

» बीपीएल परिवारों की किशोरियों, महिलाओं को मुफ़्त सेनेटरी पैड उपलब्ध करवाने के लिए महिला एवं किशोरी सम्मान योजना चलाई जा रही है। स्कूलों में भी छात्राओं को सेनेटरी पैड उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

राजस्व में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, प्रथम तिमाही में पिछले साल की तुलना में 21 प्रतिशत वृद्धि हुई है। आबकारी एवं कराधान विभाग के इस वर्ष अप्रैल-जुलाई तक में राज्य का कुल कर-संग्रह 23,108 करोड़ रुपए जा पहुंचा है।

स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बताया कि जो छात्र नौवीं कक्षा में एक पेड़ लगाएंगे और 12वीं कक्षा तक उसकी देखभाल करेंगे, उन्हें 12वीं की परीक्षा में 1-5 अंक अतिरिक्त मिलेंगे।

पंचायतों में निरक्षरता से आज़ादी

आज़ादी के बाद 75 साल की अवधि बीत जाने के बाद भी गांवों का विकास प्राथमिकता है। विगत करीब नौ सालों में हरियाणा में गांवों के विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई गईं जिनको अमलीजामा पहनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें विशेष सहयोग कर रहे हैं गांव के पढ़े लिखे जन प्रतिनिधि। अनपढ़ या कम पढ़े लिखे सरपंच, पंच या अन्य प्रतिनिधि अब गुजरे जमाने की बात हो गई है।

ग्राम पंचायतें राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, सुशासन और लोकतंत्र का रक्षा कवच हैं। देश में पंचायतों की न्यायप्रियता के कारण 'पंच-परमेश्वर' की धारणा बनी थी। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये तीनों स्तर देश की प्रजातंत्र व्यवस्था के मूल आधार हैं। इसी प्रकार नगरपालिका व नगर परिषद जैसे स्थानीय निकाय भी देश के शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास में सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। इससे शहरों और गांवों के स्तर पर वहां की जरूरतों की पहचान करके और उन आवश्यकताओं की प्राथमिकता तय करके विकास के कामों को चलाया जा रहा है। आज हरियाणा में पढ़ी-लिखी पंचायतें कारगर

भूमिका निभा रही हैं। मनोहर सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही यह निर्णय ले लिया था कि ग्रामीण क्षेत्र का समुचित विकास तभी संभव है जब गांव के प्रतिनधि पढ़े लिखे होंगे। तब से लेकर आज तक पढ़ी - लिखी पंचायतें अपने गांव के विकास पर पूरा ध्यान दे रही हैं।

ग्रामीण आँचल के गतिशील विकास हेतु पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण किया गया है। इसी के चलते सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को बड़ी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां दी गयी हैं। पंचायती राज संस्थानों को 10 प्रमुख विभागों का काम सौंपा गया है और विकास कार्यों के लिए ग्रांट की राशि सीधे पंचायतों के खातों में जमा करवाई जा रही है। विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए ई-टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। पांच लाख रुपए तक के कार्य करवाने की शक्ति सरपंच को दी गई है।

पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति के मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर स्टाम्प शुल्क का अधिभार लगाया गया है। निर्वाचित

> "राष्ट्र की आत्मा गांवों में बसती है और हमारी अर्थव्यवस्था अब भी खेती बाड़ी पर ज्यादा निर्भर है। इसलिए गांवों के चहुंमुखी विकास के बिना प्रदेश और देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में पंचायती राज संस्थाएं न केवल मजबूत हुई हैं, बल्कि अधिक शक्ति यां मिलने से सशक्त और सशक्त हुई हैं।
>
> **- मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा**

प्रतिनिधियों व ग्रामीणों के बीच समन्वय के लिए 'ग्राम दर्शन' पोर्टल शुरू किया गया है।

पोर्टल के जरिए कोई भी नागरिक अपने गांव की समस्या या मांग का जिक्र राज्य सरकार से कर सकता है। संबंधित विभाग के अधिकारी उस पर संज्ञान लेते हैं। **- मनोज प्रभाकर**

बिजली संकट से आज़ादी

प्रदेश में बिजली संकट अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से 90 प्रतिशत से अधिक गांवों में 24 घंटे बिजली सप्लाई हो रही है। अब वह बात नहीं कि तीसरे या चौथे दिन बिजली आएगी तो ही पशुओं के लिए चारा कटेगा या पानी भरा जाएगा। पढ़ने वाले बच्चे दिन के साथ साथ रात को भी खूब पढ़ रहे हैं।

हरियाण के बिजली विभाग के उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। 'पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके। हरियाणा में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया भी जारी है। सरकार द्वारा चलाई जा रही 'जगमग योजना' के अंतर्गत भी गांवों में चौबीस घंटे बिजली की सप्लाई करवाई जा रही है। प्रदेश की लगभग 10 हजार ढाणियों में बिजली उपलब्ध करवाने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है।

राज्य सरकार ने प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं हेतु कृषि ट्यूबवैल कनैक्शन के लिए स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना-2023 शुरू की है। इस योजना के तहत, उपभोक्ता को अपना लोड बढ़वाने के लिए 100 रुपए प्रति किलोवाट की दर से जमा करवाने होंगे। राज्य सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए बिल माफ़ी योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत वे सभी अंत्योदय परिवार पात्र होंगे, जिनकी पीपीपी डाटा के अनुसार सत्यापित आय प्रति वर्ष एक लाख रुपए तक है।

पराली के धूएं से आज़ादी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं काफी कम हुई हैं। किसानों को ज़ागरूक करने के साथ-साथ विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के फलस्वरूप पराली जलाने की घटनाओं में लगभग 48 प्रतिशत तक कमी आई है।

कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के मुताबिक 'फसल अवशेष प्रबंधन' योजना के तहत राज्य सरकारों को 3,138 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और राज्य सरकारों द्वारा 2,675 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 2,42,000 से अधिक मशीनें व उपकरण खरीदे गए हैं। पिछले वर्ष प्रदेश में 3,661 ऐसी घटनाएं रिपोर्ट हुई।

हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की समस्या को गंभीरता से लिया है और केंद्र सरकार के सहयोग से पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने में काफी सफलता पाई है। 'फसल अवशेष प्रबंधन योजना' के तहत इन-सीटू मैनेजमेंट के लिए वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक किसानों को 80 हजार मशीनें वितरित की गई हैं। इस वर्ष भी 2 अगस्त, 2023 तक लगभग 21 हजार से अधिक किसानों ने मशीनों के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा, कस्टम हायरिंग सेंटर की ओर से भी मशीनों की मांग आई है। इन मशीनों की लागत लगभग 328 करोड़ रुपए बनती है।

एक्स-सीटू मैनेजमेंट के तहत भी 2जी एथनोल प्लांट में पराली का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा धान के स्थान पर कम पानी की खपत वाली फसलों की खेती करने के लिए किसानों को 7 हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

पराली जलाने वाले 2,641 लोगों पर 61.90 लाख रुपए ज़ुर्माना व एफआईआर दर्ज़ की गई। 2016-17 में पराली जलाने की लगभग 15,686 घटनाएं हुई थी। 2021-22 में 6,987 घटनाएं हुई।

राज्य सरकार ने जीरो बर्निंग के लिए विशेष प्रोत्साहन देने के लिए भी योजना बनाई है। इसके अंतर्गत, रेड जोन में जो पंचायत अपने क्षेत्र में पराली जलाने की एक भी घटना नहीं होने देती, उस पंचायत को एक लाख रुपए दिए जाते हैं। येलो जोन में 50 हजार रुपए की राशि दी जाती है।

जीएसटी काउंसिल द्वारा ऑनलाइन गेमिंग चाहे वह कैसिनो में हो या बेटिंग अथवा होर्स रेसिंग आदि पर इस्तेमाल होने वाले पैसे को 28 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में डालने की सहमति बनी है। इससे देश को ज़्यादा राजस्व मिलेगा।

राज्य सरकार की मदद से चालू वित वर्ष के दौरान सहकारी चीनी मिलों ने 490 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद, जिसकी 1,819 करोड़ रुपए की राशि देय बनती है का किसानों को भुगतान कर दिया है।

अमृत भारत स्टेशन

'अमृत भारत स्टेशन' योजना के तहत हरियाणा जिन 15 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाना है, उनमें अंबाला सिटी, भिवानी जंक्शन, फरीदाबाद, पटौदी रोड, हिसार, बहादुरगढ़, जींद जंक्शन, नरवाना जंक्शन, नारनौल, कालका, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर-जगाधरी शामिल हैं। इसके अलावा, योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के 34 स्टेशनों को भी शामिल किया जाएगा।

-मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'अमृत भारत स्टेशन' योजना के तहत प्रदेश के 15 रेलवे स्टेशनों को योजना में शामिल किया गया है। पिछले लगभग नौ वर्षों के दौरान देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, चाहे वह सड़क तंत्र हो या रेलवे तंत्र हो या हवाई क्षेत्र और समुद्री मार्ग की बात हो। हरियाणा को इसमें भौगोलिक दृष्टि का लाभ मिला है तथा केजीपी व केएमपी के पूरा होने के बाद दिल्ली का यातायात पर दबाव कम हुआ है। प्रदेश को 17 राष्ट्रीय राजमार्ग मिले हैं, जिनमें से आठ का कार्य पूरा हो चुका है। अब प्रदेश का हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है, जो आर्थिक कनैक्टिविटी व समृद्धि का प्रतीक है।

देश के भौगोलिक क्षेत्र में हरियाणा का क्षेत्रफल लगभग 1.3 प्रतिशत और जनसंख्या में 2.90 प्रतिशत होने के बावजूद भी देश के सकल घरेलू उत्पाद में चार प्रतिशत का योगदान दे रहा है।

पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक, बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना पूरे राष्ट्र के लिए यह बहुत बड़ी सौगात है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि रेलवे में एक साथ 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य शुभारंभ होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा व चंडीगढ़ के साथ-साथ पंजाब को भी इस योजना का फ़ायदा होगा क्योंकि योजना के तहत पंजाब के भी 22 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा।

» रेलवे तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलमेंट ऑथिरिटी का गठन।
» रेलवे मंत्रालय के साथ एमओयू किया है, जिसके तहत स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन।
» रोहतक में देश का पहला पांच किलोमीटर लंबाई का ऐलिवेटिड रेलवे ट्रैक।
» कुरुक्षेत्र में ऐलिवेटिड रेलवे ट्रैक का कार्य लगभग पूरा, कैथल के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार।
» पलवल से सोनीपत तक हरियाणा ऑरबिट रेलवे कॉरिडोर को मंजूरी।
» मैट्रो कनैक्टिविटी का भी विस्तार किया जा रहा है।
» सोनीपत में रेलवे कोच फैक्टरी की सौगात।
» ईस्टर्न-वेस्टर्न डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर बनने से हरियाणा में सड़क तंत्र का जाल बिछा।

अस्वच्छता से आज़ादी

ओडीएफ प्लस ग्रामीण अभियान के तहत सभी घटकों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरुरत है ताकि गांवों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का सही निष्पादन हो सके। इसके लिए राज्य के 4 हजार गावों में अपशिष्ट पृथक्करण शेड बनाने का कार्य जारी है। पानीपत, भिवानी, फरीदाबाद में संतोषजनक कार्य हुआ है। अधिकारियों को सोलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ-साथ सफाई व्यवस्था पर भी पूरा फोकस रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण एवं उपयोग पर भी बल दें ताकि नागरिकों को साफ एवं स्वच्छ वातावरण उपलब्ध हो सके।

शौचालयों के मल कीचड़ प्रबंधन के लिए दूसरा गड्ढा खोदने के लिए भी 5 हजार रुपए की राशि सरकार द्वारा मुहैया करवाई जा रही है।

शौचालयों के मल निष्पादन के लिए जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा चार जिलों में सर्वे करवाया जा चुका है, शेष जिलों में भी जल्द सर्वे करवाकर इस पर कार्य किया जाएगा। इसके अलावा नहाने, कपड़े व बर्तन धोने के पानी का भी सामुदायिक तौर पर उचित निष्तारण किया जाएगा। जोहड़ एवं तालाबों में इस पानी को डालने के लिए तीन अलग-अलग गड्ढे बनाए जा रहे हैं ताकि इनमें पानी साफ़ होकर ही जाए।

राज्य के नौ जिलों में 20 से अधिक गोबर-धन प्लांट लगाए जा रहे हैं जिनमें से छह गोबर-धन प्लांट पूर्ण हो चुके हैं। इन प्लांट के कार्य की मॉनिटरिंग करते हुए छह माह में पूरा करना सुनिश्चित होगा। इसके अलावा हर खण्ड एवं जिला स्तर पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कार्य किया जा रहा है। इनके हर प्लांट पर लगभग 16 लाख रुपए की लागत आएगी जिसमें आठ रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्लास्टिक वेस्ट का निस्तारण किया जाएगा। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट योजना महाग्राम में लागू की जा रही है।

स्वच्छ भारत मिशन प्लस ग्रामीण अभियान की मासिक आधार पर रैंकिंग की जाएगी और सराहनीय कार्य करने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल 'स्वच्छ भारत मिशन प्लस ग्रामीण अभियान' की समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी दी। बैठक से सभी जिलों के उपायुक्त, सीईओ जिला परिषद भी वीसी के माध्यम से जुड़े।

मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि अधिकारी 'स्वच्छ भारत मिशन प्लस ग्रामीण अभियान' के सभी घटकों पर मिशन मोड में लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करें ताकि आगामी तीन माह में लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि अक्तूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान को लेकर आयोजित बैठक में समीक्षा करेंगे। इसलिए अभियान को गति देकर राज्य को ओडीएफ प्लस बनाने की दिशा में बेहतर कार्य करने की जरुरत है।

खेलों में परचम लहराने की आज़ादी

» सरकार की खेल नीति खिलाड़ियों को अधिकतम नकद पुरस्कार तथा सुविधाएं देने में पूरे देश में उत्तम है।
» उत्कृष्ट खिलाड़ी पॉलिसी के तहत राजकीय नौकरियों में खिलाड़ियों की नियुक्ति का प्रावधान।
» सोनीपत में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना।
» ओलंपिक खेलों में स्वर्ण विजेता को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेता को 2.50 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार तथा प्रत्येक प्रतिभागी खिलाड़ी को 15 लाख रुपए देने का प्रावधान है।
» ओलंपिक खेलों हेतू चुने गए हरियाणा के खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार राशि में से प्रशिक्षण तथा खुराक हेतू अग्रिम 5 लाख रुपए देने का प्रावधान है।
» पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी ओलंपिक पदक विजेताओं की तरह प्रतिभागिता करने पर सामान्य खिलाड़ियों की भांति नकद पुरस्कार की बराबर राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
» विश्व की 10 अधिकतम ऊंची/जटिल चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले खिलाड़ियों को 5.00 लाख रुपए का नकद ईनाम तथा ग्रेड-सी का खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र देने का प्रावधान किया है।
» आगामी एशियन/पैरा एशियन तथा कॉमनवैल्थ/पैरा कॉमन वैल्थ खेलों के प्रतिभागी खिलाड़ियों को 2.50 लाख रुपए की अग्रिम तैयारी राशि प्रदान की जाएगी।
» ध्यानचंद, द्रोणाचार्य, अर्जुन अवार्डीज का मानदेय 5,000/-रुपए प्रतिमास से बढ़ाकर 20,000/-रु. प्रतिमास किया गया है।
» तेनजिंग नोर्गे अवार्डी को 20,000/-रुपए की तरह ही भीम अवार्डी को भी 5,000/- रुपए प्रतिमास मानदेय दिया जा रहा है।
» गत 4 वर्ष से लंबित भीम अवार्ड 52 योग्य अवार्डीज को महामहिम राज्यपाल के करकमलों से प्रदान किया गया, जिसमें प्रति अवार्डी 5.00 लाख रुपए नकद, 01 ब्लैजर, टाई/स्कार्फ, स्क्रोल तथा भीम प्रतिमा सहित कुल 2.60 करोड़ रुपए के नकद राशि दी गई।

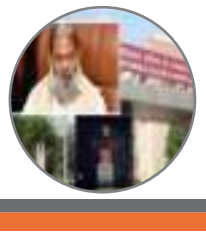

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज, करनाल के बैचलर ऑफ फिजियोथैरेपी के छात्रों को पांच हजार रुपए प्रतिमाह की दर से इंटर्न वजीफ़ा देने की मंजूरी प्रदान हुई है।

पंचकूला सेक्टर-23 के कूड़े कचरे का जैविक उपचार करने के लिए दो मशीने लगाई जा रही हैं जिसका निष्पादन मार्च 2024 तक कर दिया जाएगा। इसके लिए 3 लाख एमटी कचरे का निष्पादन किया जाना है।

नशे से आज़ादी

हरियाणा से नशे की बुराई को जड़ से खत्म करने की दिशा में प्रदेशव्यापी नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं का भी भरपूर सहयोग लिया जा रहा है। इस मुहिम को गांव, स्कूल, कॉलेज स्तर से ही सक्रिय कर हर व्यक्ति को नशा मुक्त अभियान से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भजनों, नाटकों द्वारा नशे के दुष्प्रभावों के बारे लोगों को ज़ागरूक किया जा रहा है। नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी बनाने के लिए नई टास्क फॉर्स भी बनाई जा रही है, ताकि नशे पर पूर्ण रूप से अंकुश लग सके। हरियाणा पुलिस द्वारा नशा बेचने वालों के खिलाफ़ पूरी सख़्ती बरती जा रही है।

प्रयास

» राज्य सरकार नशे पर रोक लगाने के लिए निरंतर योजनाएं बना रही है।

» प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस अभियान में सहयोग की निष्ठा जताई है।

» हरियाणा राज्य मादक पदार्थों के सेवन को रोकने के लिए सोसाइटी की स्थापना की गई है।

» सोसाइटी के लिए एक करोड़ रुपए का वार्षिक अनुदान दिया गया है।

» नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत में हरियाणा के 10 जिलों को शामिल किया गया था।

» जून 2023 तक प्रदेश में कुल 105 नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं।

» दवाओं की अवैध बिक्री को रोकने हेतु मोबाइल ऐप साथी बनाया है।

» अंतरराष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर राज्य भर में लगभग 101 करोड़ रुपए से अधिक के मादक पदार्थों का निस्तारण किया गया है।

» पंचकूला में अंतरराज्यीय ड्रग सचिवालय की स्थापना।

» हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाने की योजना।

सेहत की चिंता से आज़ादी

इसमें कोई दोराय नहीं कि आज स्वास्थ्य सेवाओं में निजी क्षेत्र ने तरक्की की है लेकिन सरकारी सेवाओं को भी निजी क्षेत्र के सामान लाकर खड़ा करने के प्रयास जारी हैं। नागरिकों का ईलाज सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में भी सहजता से हो सके, इस पर कार्य किया जा रहा है।

अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री

हरियाणा देश का प्रथम राज्य है जहां स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मैपिंग कराई जा रही है। आज तक स्वास्थ्य सेवाएं डिमांड बेस रही हैं मगर राज्य सरकार चाहती है कि आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। डब्ल्यूएचओ के मापदंडों के अनुसार किस स्थान पर कितने बिस्तरों वाले अस्पताल, सुविधा, डॉक्टर इत्यादि की जरूरत हो इसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है।

हरियाणा के हर जिले में मेडिकल कालेज बनाया जा रहा है और छह जिलों में नए कालेज बन कर तैयार हो रहे हैं, अन्य जिलों में भी कार्य प्रगति पर है। विभाग में मेडिकल व पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती की गई हैं।

प्रदेश के गरीब परिवारों की मदद के लिए आयुष्मान योजना से संबंध चिरायू योजना शुरू की गई है जिससे प्रदेश के 29 लाख परिवारों के लाभान्वित होने की संभावना है। गरीब परिवार के लोगों को उपचार की चिंता रहती थी, जो अब नहीं है। बड़े चिकित्सा संस्थानों के अलावा बड़े पैमाने पर हैल्थ वैलनेस सेंटर खोले गए हैं। पीएचसी, सीएचसी स्तर पर एमबीबीएस डाक्टर के अलावा डेंटल सर्जन की व्यवस्था की गई है। जहां कोई भी नागरिक अपने उपचार फ्री में करा सकता है। अधिकतर दवाइयां भी मुहैया कराई गई हैं।

हरियाणा में इस बार सेहत की देखभाल के लिए 9 हजार 600 करोड़ रुपए बजट रखा गया है। सरकारी अस्पतालों में सिटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड की सुविधा मुहैया करवाई जा रही हैं। कुछ अर्से पहले सरकारी क्षेत्र में केवल कुछेक दवाइयां मिलती थी, अब अस्पतालों में डब्ल्यूएचओ जीएमपी मान्यता प्राप्त दवाई मिल रही हैं। चिकित्सा संस्थानों में यूएस एफडीए द्वारा सर्टिफाइड उपकरण लगाए जा रहे हैं।

राज्य सरकार के प्रयासों के अनुरूप पहले इम्पैनलमेंट सिफारिश के आधार पर होती थी, अब एनएबीएच सर्टिफाईड अस्पतालों को इम्पेनेल्मेंट करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से आज हरियाणा के 600 अस्पताल एनएबीएच सर्टिफाइड हो गए हैं और 500 के करीब अस्पताल इम्पैनलमेंट हैं जो एनएबीएच सर्टिफाइड हैं।

शिक्षा क्षेत्र में ऊंची उड़ान

संगीता शर्मा

हरियाणा सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग और यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज रीजनल कॉलेज के मध्य एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए जिसके तहत अब हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले युवाओं को कैम्ब्रिज रीजनल कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिलेगा तथा प्रोफ़ेसरों को भी ट्रेनिंग लेने का मौका दिया जाएगा। कैम्ब्रिज रीजनल कॉलेज के युवा भी हरियाणा के कॉलेजों में पढ़ाई कर सकेंगे। बतादें कैम्ब्रिज रीजनल कॉलेज इंग्लैंड के टॉप -10 कॉलेजों में शुमार है।

उम्मीद जताई गई है कि यह एमओयू हरियाणा के युवाओं के सुदृढ़ भविष्य के नए द्वार खोलेगा। इससे राज्य की शिक्षा ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड के मानक स्तर की होगी, विदेशों के अधिक से अधिक युवा हरियाणा में भारतीय-विद्या, भारतीय भाषाएं दवाओं का आयुष सिस्टम, योग, आर्ट्स, संगीत, इतिहास, संस्कृति तथा आधुनिक भारत के विषय पढ़ने आएंगे।

उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा के मुताबिक राज्य सरकार का यह कदम प्रदेश के युवाओं और सरकारी कॉलेज के प्रोफ़ेसरों की स्किल में बढ़ोतरी करेगा। हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने कहा कि यह प्रोजेक्ट 'ग्लोबल ट्रेनिंग एजुकेशन प्रोग्राम' और किंग्समीड द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। इस एमओयू से प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले युवाओं को इंडस्ट्रीज की ज़रूरत के अनुसार आधुनिक स्किल से अपडेट होने में सहायता मिलेगी और उनको आसानी से रोज़गार मिलेगा।

उच्चतर शिक्षा का विविधिकरण करके इसे और अधिक बढ़ावा दिया जाए, यह हमारी नई शिक्षा नीति का भी एक हिस्सा है। हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग और यूनाइटेड किंगडम के कैंब्रिज रीजनल कॉलेज ने रोज़गार-कार्यक्रम, खेल शिक्षा, अंग्रेज़ी भाषा कार्यक्रम, छात्र-विनिमय समर स्कूल और शिक्षक-प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता किया है। दोनों संस्थाएं मिलकर जॉब प्लेसमेंट, स्वरोज़गार, एंटरप्रेन्योरशिप तथा इन्क्यूबेशन के लिए प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के युवाओं तथा फैकल्टी को तैयार करने में सफ़ल होंगी।

-मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

शिक्षा

» वर्ष 2025 तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य।
» प्रदेश में एक किलोमीटर में प्राथमिक, तीन किलोमीटर में माध्यमिक विद्यालय।
» आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले-वे में बदला।
» नये मॉडल क्रेच खोलने का काम जारी।
» बैग फ्री राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल खोले।
» सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को मुफ़्त कोचिंग हेतु सुपर-100 कार्यक्रम।
» सरकारी स्कूलों के पांच लाख विद्यार्थियों को मुफ़्त टेबलेट।
» चिराग योजना के अंतर्गत बच्चों का मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में दाखिला।
» बच्चों की नींव मज़बूत करने के लिए पहली से तीसरी कक्षा तक फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कार्यक्रम शुरू।

उच्चतर शिक्षा

» 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज स्थापित।
» केजी से पीजी तक चार विश्वविद्यालयों में दाखिले।
» पोस्ट ग्रेजुएशन तक लड़कियों की ट्यूशन फीस माफ़।
» व्यावसायिक व तकनीकी कोर्सों के लए क्रेडिट ग्रारंटी स्कीम।
» हिंदी भाषा में बी.टेक पाठ्यक्रम तीन विश्वविद्यालयों में शुरू।
» ई-कर्मा, हर साल 3,000 उम्मीदवारों को चार-छह महीने का मुफ़्त प्रशिक्षण।
» मुरथल (सोनीपत) में सीआईईपीटी व पंचकूला में निफ्ट स्थापित।

हरियाणा में अब लीवर और किडनी से संबंधित गंभीर बिमारियों के इलाज के लिए मरीजों को जल्द ही पीजीआईएमएस, रोहतक में लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा मिलेगी।

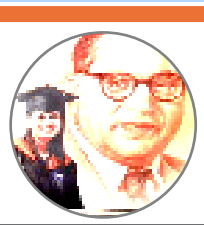

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से वर्ष 2023-24 के अंतर्गत डॉ. भीमराव अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी, 2024 तक आवेदन कर सकते हैं।

इक दरख्त ऐसा मुहब्बत का लगाया जाए

डा. चंद्र त्रिखा

यह एशिया के उस भूखण्ड की गाथा है जिसने विदेशी दास्तां से मुक्ति के लम्हों में जश्नों व त्रास्दियों को एकसाथ जिया, भोगा और अपने नवनिर्माण की यात्रा उमंगों व मर्मान्तक पीड़ाओं के परिवेश में शुरू की। इसी भूखण्ड में करोड़ों आबाद लोगों ने, नए आशियानों के लिए अपने भरे पूरे घर छोड़े। यह प्रि या अब भी इतिहास में सबसे बड़े 'आबादी माइग्रेशन' के रूप में बयान होती है। 14 अगस्त, 1947 से पूर्व जो भूखण्ड एक भरा पूरा देश था, अब उसका भूगोल बिल्कुल बदल चुका है। अब वह भूखण्ड तीन स्वतंत्र प्रभुसत्ता सम्पन्न देशों में विभाजित है।

जब अतीत एक हो, विरासत सांझी हो, सांस्कृतिक जिंदगी एक जैसी हो, आर्थिक विषमताओं का स्तर एक जैसा हो, जंगल, नदियां, वनस्पति, मिट्टी की गंध, मुहावरे, दुआएं, प्रार्थनाएं और गालियां कमोबेश एक जैसी हों तो अलगाव का अलाव जलाना आसान नहीं होता। मगर अलग अलख जले। और अब उन्हीं अलावों की रौशनी में ज़िन्दगी जीने का करीना तय हो चुका है।

तीनों में, आकार व आबादी की दृष्टि से 32 लाख 87 हज़ार 263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला मुख्य राष्ट्र हमारा भारत है। यद्यपि इसके 78114 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर पाकिस्तान का कब्जा है। उसमें से 8180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान ने अवैध रूप से चीन को दे दिया है। चीन के कब्जे में वैसे भी 37555 वर्ग किलोमीटर का हमारा क्षेत्र है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश भी है और इन तीनों विभाजित भूखण्डों में भी सबसे बड़ा है। 14 अगस्त, 1947 को भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आने वाला देश पाकिस्तान इस समय 7,96,095 वर्ग किलोमीटर में फैला है।

1971 से पूर्व यह देश इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ पाकिस्तान था। मगर बांग्लादेश के स्वतंत्र अस्तित्व में आने के बाद यह देश सिकुडक़र छोटा हो गया। अपनी ढेरों विसंगतियों एवं अस्थिर राजनैतिक तंत्र के बावजूद पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र है और अपने अस्तित्व के लिए निरंतर जूझ रहा है।

तीसरा खण्ड 1971 में अस्तित्व में आया। बांग्लादेश के रूप में यह स्वतंत्र राष्ट्र 1971 में विश्व के मानचित्र पर उभरा। इसका क्षेत्रफल 1,48,393 वर्ग किलोमीटर है। यह भूखण्ड 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का एक अंग था और तब पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था।

वैसे कोई भी देश अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति सहज रूप में नहीं करता, मगर इस भूखण्ड में एक से तीन राष्ट्रों में विभाजित भारत, पाक व बांग्लादेश को अपने स्वतंत्र अस्तित्व में आने से पूर्व कुछ ज़्यादा ही त्रास्दियों के रक्तरंजित रास्तों से गुजरना पड़ा।

भारत-पाक विभाजन को अब भी विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या-माइग्रेशन माना जाता है। समान विरासत, सांझी संस्कृति, कमोबेश एक जैसा मुकद्दर व लगभग एक जैसे पहरावे व जीवनशैली वाले लोग आज लगभग 65 वर्ष बाद भी पीड़ा के परिवेश से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए। शरणार्थी, रिफ्यूजी, मुहाजिर, बांग्लादेशी आदि शब्द एक अभिशाप की तरह अभी भी करोड़ों लोगों पर चस्पां हैं। नफ़रत, मोहब्बत, मिलकर जीने और एक दूसरे को नेस्तनाबूद करने आदि मिले-जुले जज़्बों के साथ इस भूखण्ड के तीनों राष्ट्रों ने अपने समकालीन इतिहास की अब तक की इबारत लिखी है।

आतंकवाद, गरीबी, धार्मिक असहिष्णुता व प्राकृतिक आपदाओं से अब तक मुक्त नहीं हो पाए तीनों देश। आज भी तीनों पड़ौसियों का एक-दूसरे के घर में आना-जाना कड़ी जांच-पड़ताल के बिना मुमकिन नहीं है। तीनों पड़ौसियों में से बीच वाला भूखण्ड भारत है। उस पर दोहरी जिम्मेदारी भी है, दोहरी मार भी है। आज इतने वर्षों के तनाव के बावजूद भी हम लोग गालिब, इकबाल, टैगोर, फ़ैज़, काज़ी नज़रुल इस्लाम, यशपाल, कृष्ण चन्दर, मंटो, अमृता प्रीतम आदि को अपनी अदबी ज़िन्दगी से अलग करके नहीं देख पाए। नदियों के नाम वही हैं। वही सतलुज, वही रावी, ब्यास, जेहलम और चनाब। वही सिंध व सिंधु घाटी की सभ्यता, वही भर्तृहरि, गुरु गोरखनाथ, बाबा फ़रीद, वही बाबा गुरु नानक, बुल्लेशाह, ख्वाजा गरीब नवाज़, वारिस शाह। हम इन सबकी सांझेदारी से मुक्त तो नहीं हो पाए। इन्हें बांटना भी नामुमकिन रहा।

दोनों देश अब हकीकत हैं। अलग-अलग भौगोलिक इकाइयां हैं। मगर बकौल निदा फ़ाजली, अब,

इक दरख्त ऐसा मुहब्बत का लगाया जाए,
जिसका हमसाए के आंगन में भी साया जाए।

हरियाणवी कविता में राष्ट्रीय चेतना

हरियाणवी कविता की परंपरा प्राचीन है। कुछ विद्वान हरियाणवी कविता का इतिहास भी हिंदी कविता के समानांतर मानते हैं। श्री राजाराम शास्त्री ने हरियाणवी कविता का आरंभ सातवीं-आठवीं सदी से माना है। अधिकांश विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि हरियाणवी और उसकी बोलियों का प्रभाव नाथ साहित्य से लेकर भक्तिकाल की संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम काव्य धारा एवं कृष्ण काव्य धारा में रहा है।

जहां तक आधुनिक हरियाणवी कविता का प्रश्न है उसे स्वतंत्रता के बाद से माना जा सकता है। आधुनिक हरियाणवी कविता में राष्ट्रीय चेतना, हरियाणवी संस्कृति का उद्घाटन, धार्मिक भावना आदि प्रवृत्तियों पर विशेष रूप से बल दिया गया है।

आधुनिक हरियाणवी कवियों ने अपनी कविताओं में हरियाणा की प्रशंसा की है। उन्होंने अपनी कविताओं में हरियाणा की पावन भूमि के साथ-साथ यहां के लोगों की जीवन-शैली की भूरी-भूरी प्रशंसा की है। इन कवियों के अनुसार हरियाणा के लोग भोले-भाले, मेहनती, सदाचारी, देश-प्रेम की भावना तथा मानवता के गुणों से भरपूर हैं।

देवी शंकर प्रभाकर ने लिखा है -

हरियाणा की पावन धरती तेरा वंदन तेरा पूजन,
तेरी माटी शीश चढ़ाकर, हम कर ले तेरा अभिनंदन

आधुनिक हरियाणवी कविता अपने समाज का यथार्थ चित्रण के साथ - साथ जीवन में व्याप्त अनेक विषमताओं पर प्रकाश डाला गया है। भौतिकतावाद के कारण समाज में बढ़ते वैमनस्य, पारिवारिक क्लेश, बेरोज़गारी के कारण व्याप्त निराशा, महंगाई, दहेज-प्रथा, कन्या-भ्रूण हत्या आदि विषयों को भी कविता में स्थान दिया गया है। साथ ही प्रेम, सदभाव, व त्याग जैसे उदात्त गुणों को जीवन में अपनाने पर बल दिया गया है।

भारत भूषण सांघीवाल लिखते हैं-

जिस घर में एक्का नहीं, रोज़ रहे तकरार
नहीं कदे भी हो सकै, उसका बेड़ा पार

स्वतंत्रता से पहले हरियाणवी कविता में राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा मिलती है। स्वतंत्रता के पश्चात की हरियाणवी कविता में देश की स्वतंत्रता की रक्षा और विकास के लिए भी भारतीयों को प्रेरित किया गया है।

सांघीवाल लिखते हैं-

भारतवासी भारत की तम लाज बचाइयो
भाइयो, गोरयां के पैण्यां तै, मां न छुटवाइयो
जब मां के बेटे सां हम सब भाई-भाई
हिंदू-मुसलमान चाहे हों सिक्ख-ईसाई ।

भक्ति-भावना हरियाणवी कवियों की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। हरियाणवी कवियों ने अपनी काव्य-रचनाओं में विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, गणेश, बुद्ध आदि देवी-देवताओं की महिमा के गान के साथ -साथ देवी-देवताओं की लोक-प्रचलित कथाओं व प्रसंगों का वर्णन किया गया है।

आधुनिक हरियाणवी कविता का कला-पक्ष भी भाव-पक्ष की भांति उत्कृष्ट है। हरियाणवी कवियों ने प्रदेश की लोक-भाषा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। हरियाणवी कविता में मुख्यतः हरियाणवी भाषा का प्रयोग हुआ है जिसमें तत्सम तथा तद्भव शब्दों के साथ-साथ देशी-विदेशी शब्दों का प्रयोग देखा जा सकता है। मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा आकर्षक, स्वाभाविक तथा प्रभावोत्पादक बन गई है। जहाँ तक शैली का प्रश्न है, आधुनिक हरियाणवी कवियों ने वर्णनात्मक, संबोधन, प्रतीकात्मक, आत्मकथात्मक, विवरणात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है।

-संवाद ब्यूरो

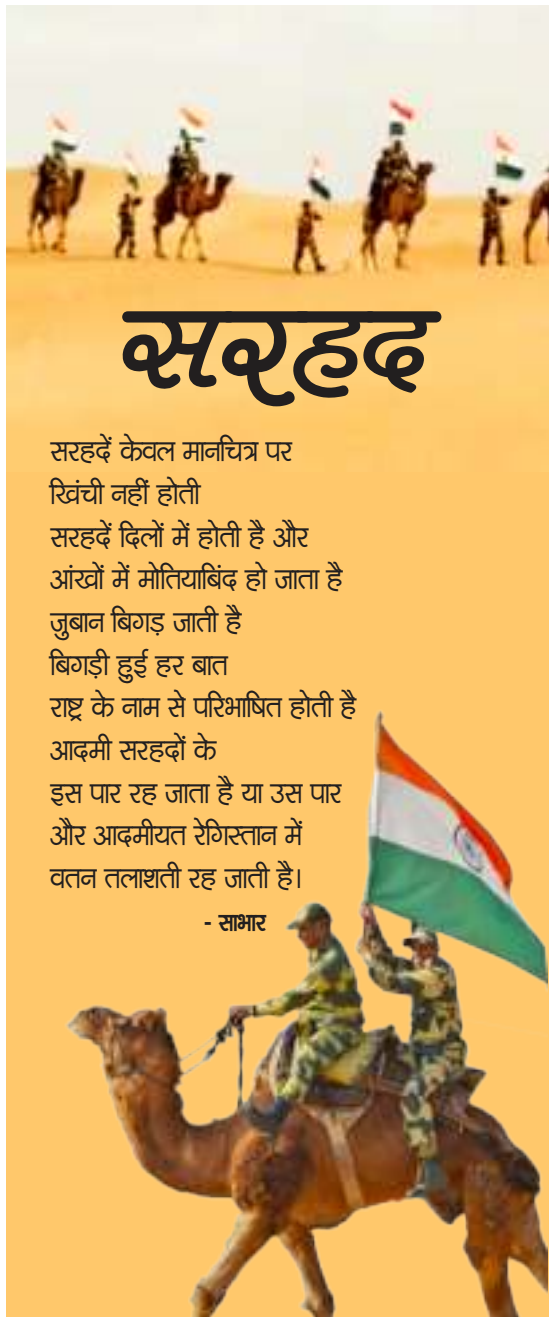

सरहद

सरहदें केवल मानचित्र पर
खिंची नहीं होती
सरहदें दिलों में होती है और
आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है
जुबान बिगड़ जाती है
बिगड़ी हुई हर बात
राष्ट्र के नाम से परिभाषित होती है
आदमी सरहदों के
इस पार रह जाता है या उस पार
और आदमीयत रेगिस्तान में
वतन तलाशती रह जाती है।

- साभार

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com